



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roc.lko-mef@gov.in, m\_env@rediffmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./04/51/2014/एफ.सी/096

दिनांक: 10.09.2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव(वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग),  
अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,  
लखनऊ।

(आर्गोलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Trans/4276/2013)

विषय: 400 के०वी० डबल सर्किट बरेली-काशीपुर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु रामपुर में 0.6348 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 53 वृक्षों के पातन एवं पीपली वन ब्लाक की 25.0746 हे० आरक्षित वन भूमि कुल 25.7094 हे० वन भूमि तथा बरेली वन प्रभाग में 0.1564 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों के पातन, इस प्रकार परियोजना में कुल 25.8658 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 59 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-94/81-2-2020-800(71)/2014, दिनांक-02.09.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-1104/14-2-2014-800(71)/2014 दिनांक-20.06.2014 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-16.12.2014 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी, जिसकी अनुपालन आख्या उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। उक्त क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 400 के०वी० डबल सर्किट बरेली-काशीपुर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु रामपुर में 0.6348 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 53 वृक्षों के पातन एवं पीपली वन ब्लाक की 25.0746 हे० आरक्षित वन भूमि कुल 25.7094 हे० वन भूमि तथा बरेली वन प्रभाग में 0.1564 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों के पातन, इस प्रकार परियोजना में कुल 25.8658 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 59 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 51.7316 ha. degraded forest land (Compartment No. Not provided, Danidia Reserve Forest Block, Bilaspur Range Rampur Forest Division. District- Rampur) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
4. State Government shall raise penal compensatory afforestation over an area of 77.28 ha. of degraded forest land from funds realized from the user agency.
5. The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.
6. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25-2012-FC dated 05.05.2014 & 19/11/2014.
7. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

8. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
9. No labour camp shall be established on the forest land.
10. Plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in ROW under transmission line shall be taken up by forest department at the cost of User agency.
11. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
12. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
13. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
14. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
15. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
16. The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the Court orders, provisions, rules, regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.
17. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
18. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
19. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

भवदीया,

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो० आफ़े इण्डिया लि०, अखिल हृदयकुंज रानी पद्मादेवी कालोनी, मानपुर रोड, काशीपुर, उत्तराखण्ड।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

 10.09.2020  
(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}